सामाजिक बदलाव में सामुदायिक रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट

—हेमंत जोशी

देश में पिछले दो दशकों से चल रही बदलाव की बयार से ग्रामीण भारत भी अछूता नहीं रहा है। इन दो दशकों में गांवों की तस्वीर बदली है, लोगों का रहन-सहन बदला है और इसमें संचार माध्यमों के प्रसार के साथ-साथ भारत सरकार की अनेक योजनाओं का विशेष योगदान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं ने तो गांवों का जीवन बेहतर किया ही है, जनसंचार माध्यमों की बहुआयामी पहुंच और गांव के लोगों द्वारा इन माध्यमों के उपयोग ने गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी कम किया है।

पिछले दिनों अप्रैल में जारी की गई भारत के इंटरनेट और मोबाइल संघ (IAMI) और भारतीय बाजार शोध कार्यालय (IMRB) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ग्रामीण भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग शत–प्रतिशत बढ़ा और सवा करोड़ उपभोक्ताओं से बढ़कर गाँवों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपभोक्ता ढाई करोड़ हो गए। इसकी तुलना में शहरों में सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की संख्या 11 करोड़ 80 लाख के करीब है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में गांवों की इस भागीदारी का असली श्रेय भारत में फैलते हुए मोबाइल उद्योग को जाता है जिसकी वजह से आज भारत में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 97 करोड़ से अधिक हो चली है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 42 करोड़ से कुछ ज्यादा की है।

मोबाइल संप्रेषण का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हुआ है क्योंकि इस साधन के लिए उनके गांव तक टेलीफोन के तार पहुंचने का उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा और कम लागत पर और कम किराए पर आसपास के गांवों और शहरों के लोगों से संपर्क करने की सुविधा उन्हें मिली। बैटरी से चलने वाले इन यंत्रों का प्रचलन गांवों में इसलिए भी बढ़ा कि जिन गांवों में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है वहाँ भी मोबाइल न केवल बातचीत के काम आता है बल्कि रेडियो और रिकार्ड किए हुए गाने मुहैया कराता है।

एफ. एम और सामुदायिक रेडियो के प्रसार ने भी गांवों में जीवन में बदलाव लाने में बहुत मदद की है। पिछली बार जब पूरे भारत को टेलीविजन से जोड़ने के प्रयास किए गए थे तब लोगों तक सरकार और विकास से जुड़ी सूचनाएं गांव–गांव तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने हाईपावर और लो–पॉवर ट्रांसमीटर लगाए गए थे। और इनके लगने के कुछ वर्ष बाद ही उपग्रह और केबल टीवी का जिस तरह फैलाव हुआ उसने भारत के शहरों और गांवों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का माहौल ही बदल दिया। लेकिन इस शताब्दी के आरंभ में एफ.एम रेडियो का व्यावसायिक स्तर पर विस्तार हुआ और उसके तुरंत बाद जनप्रसार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक रेडियो की स्थापना देशभर में हुई और अनेक गैर–सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने गांवों के समुदायों को लक्षित करते हुए

सामुदायिक रेडियो और ग्रामीण भारत

सामुदायिक रेडियो से तात्पर्य है कि ऐसी सामग्री का प्रसारण करना जो स्थानीय/विशिष्ट श्रोताओं की मुख्य आवश्यकता है, जिनकी अनदेखी वाणिज्यिक या सरकारी जन–माध्यम प्रसारकों द्वारा की जा सकती है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पिछले दशक से सूचना क्रांति केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए देश के सर्वांगीण विकास में सामुदायिक रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत गांवों का देश होने के नाते ग्रामीण भारत में सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर अध्ययन बहुत जरूरी है।

सामुदायिक रेडियो बेजुबानों को आवाज देने का एक असाधारण तथा अदृश्य माध्यम है। यह समुदायों को अपने जीवन संबंधित मुद्दों के बारे में आवाज उठाने का अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पोषण आहार, शिक्षा तथा पंचायती राज जैसे ज्वलंत मुद्दों के बारे में सूचना प्रसारित करके सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.) लोकतांत्रिक विकास की प्रकिया को आसान बना सकते हैं। और इनके जरिए सरकारी तंत्र लाभार्थियों तक कारगर ढंग से पहुँच सकता है। इस संदर्भ में बेर्टोल्ट बेल्स ने ''रेडियो को दोतरफा संवाद का माध्यम बनाने के लिए सचमुच लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की, ताकि इससे सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

भारत सरकार की सामुदायिक नीति 2006 के अंतर्गत भारत का पहला लाइसेंसधारक 'संघम' सामुदायिक रेडियो स्टेशन 15 अक्तूबर, 2008 में स्वतंत्र रूप से मचनुर गांव में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था मचनुर गांव के दलित महिला समुदायों के विकास का रास्ता सुलभ करवाना। इस गांव के विकास के लिए अन्य जनमाध्यम की तुलना में यह असरदार बनकर उभरा है। इस संदर्भ में रेडियो के बारे में लेनिन ने कहा था, ''रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार–पत्र है।''

समग्र भारत में सामुदायिक रेडियो के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने एशियाई राष्ट्रमंडल शिक्षण केंद्र के सहयोग से 20 अक्तूबर, 2010 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इसकी परिणति यह हुई कि तमाम समुदाय प्रोत्साहित हुए और ग्रामीण भारत में अनेक सीआरएस की श्रृंखला बनती गई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं–

- **रेडियो गुड़गांव की आवाज**

इसका प्रसारण 1 नवम्बर, 2009 से शुरू हुआ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन 107.8 मेगा हर्ट्ज नागरिक समाज द्वारा संचालित एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो सप्ताह में सातों दिन 22 घंटे प्रसारण करता है। इस रेडियो स्टेशन की लहरें (रेंज) गुड़गांव उद्योग विहार के चारों ओर 10 से 15 किलोमीटर है। इस रेडियो स्टेशन पर लाखों प्रवासी श्रमिकों तथा शहरी निवासियों की आवाज, गीत, कहानियां और इन लोगों के जीवन के संघर्ष की चर्चा होती है।

- **रेडियो नमस्कार**

रेडियो नमस्कार ओडिसा (ओड़ीशा) में चल रहा पहला सामुदायिक रेडियो है। इसके कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन, खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित होते हैं।

- **रेडियो बुंदेलखंड**

रेडियो बुंदेलखंड मध्यप्रदेश का सबसे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अक्टूबर 2008 में एक गैर–सरकारी संगठन डवलपमेंट आल्टरनेटिव ने तारग्राम ओरछॉ में इसे शुरू किया। इसका उद्देश्य समुदाय के लोगों को संचार के माध्यम द्वारा सशक्त बनाने और अपने पैरों पर खड़े होने का एक जरिया उपलब्ध कराना था, जो अब तक जारी है।

- **रेडियो एक्टिव, बंगलौर**

रेडियो एक्टिव बंगलौर का पहला सामुदायिक रेडियो है। श्री भगवान महावीर मेमोरियल जैन कॉलेज, बंगलौर द्वारा 25 जून, 2007 को इसे शुरू किया गया था। यह एक शहरी रेडियो स्टेशन है, जो विविध जातियों तथा समुदायों के लोगों को सेवाएं देता है। इस स्टेशन से अपनी आवाज देने वाले सामुदायिक रेडियो जॉकी (आरजे) शिव कुमार भारत के पहले ऑटोचालक आरजे थे जो विकासात्मक मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए हर रविवार नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के साथ आमने–सामने बातचीत करते।

**(अमोल मुरलीधर निमसडकर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र)**

रेडियो केंद्र बनाए। आज देश में 179 से अधिक सामुदायिक रेडियो काम कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो की भूमिका का अभी पूरी तरह से मूल्यांकन संभव नहीं है फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर इसका दूरगामी प्रभाव होगा।

अभी 16 मार्च, 2015 को दिल्ली में आयोजित सामुदायिक रेडियो के 5वें सम्मेलन में पहली बार ये आभास हुआ कि सामुदायिक रेडियो के आगमन ने कैसे नई–नई हस्तियों को उभारा है। उस सम्मेलन में 4 ऐसी महिलाओं के नाम सामने आए जिन्होंने सामुदायिक रेडियो के जरिए ग्रामीण लोगों के बीच सफलतापूर्वक काम किया है। शांता कोष्ठी, राधा शुक्ला, गाँधीमति और सीमा भारती श्रीवास्तव ने अपने–अपने राज्यों में विकास, सामाजिक बदलाव और सशक्तीकरण के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया।

50 वर्षीय शांता पहले बीड़ी उद्योग में मजदूर थी पर अब उनका पूरा समय लोगों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने में जाता है। वह हर हफ्ते तीन–चार दिन गांव–गांव जाती हैं और स्थानीय महिलाओं और किसानों को उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करती हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले के मनीपुर गांव से 90.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित इस रेडियो को 40 गांवों के लोग लोकगीतों का कार्यक्रम सप्तरंगी, समुदाय के बुजुर्गों के अनुभव बांटने वाला कार्यक्रम वाडलो बोले छे सुनते हैं।

43 साल की सीमा भारती श्रीवास्तव आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में काम करती थी और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 90.2 मेगाहर्ट्ज पर वायस ऑफ आजमगढ़ का संचालन करती हैं। सीमा भारती इस इलाके की प्रमुख समस्या महिला–पुरुष असमानता और महिलाओं की अशिक्षा मानती हैं। वह इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अलावा महिला स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारों पर अधिक ध्यान देती हैं।

लगभग इसी उम्र की राधा शुक्ला उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के बैरी दरियाओ गांव का 'वक्त की आवाज' रेडियो चलाती हैं। वह बताती हैं कि उनका रेडियो लगभग 300 गांवों में सुना जाता है और इसमें अवधी में समाचार–पत्रिका, नाटक और क्विज़ जैसे कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। हमारा ध्यान स्वास्थ्य और कृषि पर रहता है इसलिए महिला श्रोता हमें सुनना पसंद करती हैं।

गाँधीमति की उम्र भी 43 वर्ष है और वह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के 58 गांवों के लिए प्रसारण करती हैं और इस क्षेत्र में उन्हें एफएम मैडम के नाम से जाना जाता है। पेरियार सामुदायिक रेडियो का नारा है 'सोचो, बनाओ और बदलो' और वह महिला किसानों के उद्धार और सशक्तीकरण की सफलता की कहानियां सुनाने के साथ–साथ कृषि की तकनीकों और नव–प्रयोगों के बारे में विशेषज्ञों के साक्षात्कार आदि भी प्रसारित करता है।

इसी तरह मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति की महिला रामवती ने भी रेडियो धड़कन में महत्वपूर्ण काम किया है। वह हर रोज आसपास के पांच गाँवों तक पैदल चल कर जाती हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करती हैं जिसे बाद में लोग रेडियो में सुन पाते हैं। उनका मानना है बिना जानकारियों और सूचना के बदलाव संभव नहीं है। घूंघट और परदे में ढंकी–छुपी औरतों के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने सार्थक पहल की है।

इस तरह यह दिखलाई पड़ता है कि एफएम रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट के भारतीय गांवों में प्रसार की वजह से ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है और बिजली तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के साथ मिलकर जनसंचार माध्यमों ने वहां के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने भी इन परिवर्तनों का पूरा लाभ उठाते हुए ई–प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं जिनकी मदद से ग्रामीणों की सरकार तक सीधी पहुंच हो सके और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)
ई–मेलः joshihem@gmail.com